with Ministry of Health and Family Welfare to spread message of small family, good health and on curing the ailing village population?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) The Life Line Express has been in operation since 19th July, 1991.

(b) and (c) The number of patients treated so far and the areas covered together with the sponsors are as under:

	Place	No. of Patients	Sponsored by
1.	Khilari	1568	— Central Coal Fields Ltd.
2.	Chainpur	2021	— Tata Iron & Steel Company Ltd.
3.	Farah (Mathura)	6152	— Indian Oil Corporation
4.	Amethi	3000	— Rajiv Gandhi Foundation
5.	Manmad	5000	— Bharat Petroleum

(d) The Life Line Express is presently camping at Warora (Nagpur). Thereafter, it is proposed to move to Tamil Nadu and Karnataka.

(e) There is no such proposal.

गया लोको शेड में मजदूरों की छंटनी

3497. **श्री गया सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गया लोको शेड में कार्यरत कोल (खलासी) ठेका मजदूरों की छंटनी उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद कर दी गयी है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार गड़हरा (पूर्वोत्तर रेलवे) में कार्यरत लोडरों का विभागीयकरण करने की घोषणा करेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं। चूंकि सभी कोयला और राख सम्हलाई श्रमिक सीधे ठेकेदारों द्वारा नियोजित किये जाते हैं इसलिये उन्हें रेल कर्मचारी नहीं माना जा सकता है। अतः, भाप शेड को बंद करने के बाद इन श्रमिकों को पुनः तैनात करने की कोई जिम्मेदारी लेने में रेलें असमर्थ हैं। ऐसे श्रमिकों की भर्ती/छंटनी की जिम्मेदारी ठेकेदार पर आती है।

(ख) जी, नहीं।

पूर्व रेलवे के नैमित्तिक मजदूरों का पुनर्नियोजन

3498. **श्री गया सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की पूर्व रेलवे के तीन हजार नैमित्तिक मजदूरों को पुनः नियोजित करने की कोई योजना है; और

(ख) क्या रेलवे की अपने सेवा निवृत्त कर्मचारियों को प्रतिवर्ष भारत का परिवार सहित भ्रमण करने के लिए निःशुल्क पास प्रदान करने की कोई योजना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत मानार्थ पास दिए जाते हैं जैसा कि मौजूदा नियमों में प्रावधान है।

दिल्ली में ट्रेन डिस्काइबर प्रोजेक्ट

3499. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में "ट्रेन डिस्काइबर प्रोजेक्ट" प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था और इस योजना को पूरा करने के लिए क्या समयावधि निर्धारित की गयी थी;

(ग) क्या यह परियोजना उपर्युक्त अवधि में पूरी की गयी थी;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सितम्बर, 1992 तक इस परियोजना के निर्माण के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है और इस परियोजना के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) निर्णय अगस्त, 1985 में लिया गया था। कार्य के लिए ठेका संबंधी करार पर हस्ताक्षर दिसम्बर, 1987 में किये गये थे। कार्य मई, 1991 में पूरा किया जाना था जिसमें एक वर्ष की अनुरक्षण अवधि शामिल थी।

(ग) परियोजना का अधिकांश भाग पहले ही पूरा हो चुका है। 17 स्टेशनों में से शेष 4 स्टेशनों के दूरस्थ परिचालन और स्वचल मार्ग व्यवस्थापन के कार्य मार्च, 1993 तक पूरा किये जाने की संभावना है।

(घ) विलंब मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुआ है:—

1. खाड़ी संकट के कारण नौवहन की सप्लाई अनुसूची का प्रभावित होना।
2. बे-मौसम भारी वर्षा के कारण केबल बिछाने, जोड़ लगाने तथा संतोलन के कार्यों का प्रभावित होना।
3. परियोजना जटिल किस्म की होना जो पहली बार शुरू की जा रही है।

(ङ) सितम्बर, 1992 तक खर्च की गई कुल धनराशि 29.15 करोड़ रुपये है और स्वीकृत अनुमानित लागत 29.73 करोड़ रुपये है।

Wadi Bunder Goods Depot

3500. DR. BAPU KALDATE: Will {he Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the article published in Free Press Journal. Bombay, dated 25th November, 1992 captioned: "Wadi Bunder Goods Depot to Face the Axe";

(b) how Government propose to rehabilitate the fourteen 'thousand workers who will lose their jobs on the closure of this depot;

(c) whether Government propose to construct a housing colony on that land for their employees; and if not, in what manner that land is proposed to be utilised; and

(d) what are the expansion programmes at Wadi Bunder Goods Depot?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes Sir.

(b) There is no proposal to close Wadi Bunder Goods Depot and hence the question for rehabilitation of workers does not arise.

(c) Does not arise.

(d) There is no plan, at present, for expansion of Wadi Bunder Goods Depot.

Fire services in railways

3501. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the Hindustan Times dated 4th December 1992 captioned "Railways to wind up fire services all over the country as an economy measure".

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what are the reasons therefor and whether this would involve retrenchment